

तारीख हुकम

दस्तावेजों को क्षेत्रलोकन, नजीरों  
 क्षेत्रलोकन किमा जाम शा. पत्रा।  
 जमा। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ  
 26.6.19 को पेश हो।

26.6.19. पत्रावली पेश। वकुलाम माकिम  
 सपनाप्रान के कारण पत्रावली पूर्व आ  
 नुसार दि. 07/07/2019 को पेश हो।

03/07/19 पत्रावली पेश हुई। वकुलाम फ्रीडिन उपस्थित  
 प्रशासनिक व्यक्तियों के चलते प्रकरण  
 में आदेश नहीं लिखवाया जा सका।  
 अतः वारंते आदेश पत्रावली दिनांक 05/07/19  
 को पेश हो।

05/07/19 पत्रावली आज वारंते आदेशार्थ पेश  
 हुई। वकुलाम उभय पक्ष उपस्थित।  
 प्रकरण में प्रा. पत्र अन्तर्गत 0.7, R.11  
 CPC पर बहस वकुलाम उभय पक्ष  
 पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस  
 पकील प्रार्थी (प्रा. पत्र 0.7, R.11 CPC) ने  
 तर्क प्रस्तुत किये कि वर्ष 2007 में माननीय  
 न्यायालय सलामत कलक्टर, खखेला में अनगनी  
 प्रकरण पाषुलाय व. वनाम गोकु व अन्य  
 दावा पेश हुआ, जिसमें वादिया को विवाहित  
 आराजी कबत स्क. भैराम इवारा अपनी  
 सम्पत्ति दिनांक 07/05/19 को प्रतिकारी संघ  
 को कसीमत कर दिये जाने तथा स्क. सुखराम  
 इवारा प्रतिकारी संघ. को गौद लिये जाने के  
 तथ्य की जानकारी थी, जिसको आज तक



वादिया द्वारा कहीं challenge नहीं किया गया है। उक्त वसीयत एवं गोदनामे के संबंध में वादिया की माँ का शपथ-पत्र दिनांकित 03/04/2007 भी उक्त तथ्य की ताहीद करता है। स्वयं वादिया ने भी पूर्व में न्यायालय सहायक क्लर्क, जयपुर में विचाराधीन काद में प्रतिवादी सं० 1 को दत्तक पुत्र मानते हुए शा० पं० द्वारा जारी वारिसनामा पेश किया। यदि वादिया उक्त वसीयत/गोदनामे को challenge करना चाह रही है, तो Civil Court में चाराजोही करें। अतः प्राची का प्रार्थना पत्र O.T. R. 11 CPC स्वीकार कर, दावा स्वारित करवाया जावे।

पकील प्राची की बहस के जवाब में पकील वादिया ने बखतर बहस दलील प्रस्तुत की, कि वादपत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर क्षेत्राधिकार तम होता है न कि प्रतिवादी के कयनों/जवाब दावे पर। वादिया का दावा दोषणा व स्याई निवेद्या का है। राज० कानूनकारी अधिनियम, 1955 की धारा 207 में सभी दावे एवं प्रार्थना-पत्रों के क्षेत्राधिकार का वर्णन है, जिसके तहत ही वादिया द्वारा दावा पेश किया गया है। पकील प्रतिपक्ष द्वारा तयाकथित वसीयत व गोदनामा valid है अथवा नहीं, यह अलग विषय है। विवादित छवि भूमि पैतृक है जिसकी वसीयत होना पकील प्रतिपक्ष बला रहे हैं। जबकि धारा 40 R.T. Act के अनुसार पुत्र को जन्म से ही पैतृक सम्पत्ति में हक प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार मूलक भैरु राम के पुत्र जगदीश को जन्म से ही विवादित भूमि में हक प्राप्त हो गया था, जिसकी वसीयत भैरु राम द्वारा उक्त वादिया आधिकारिक कर रही है। प्रतिवादी सं० 1 द्वारा भरी गई I.T.R में प्रतिवादी सं० 1 का दत्तक पुत्र सुजय होना अंकित नहीं है। दिनांक 03/04/2000 को एक अनुबंध मध्य लिखा हुआ है, जिसमें भी प्रतिवादी सं० 1 को दत्तक पुत्र होना वर्णित नहीं किया गया है।

तारीख हुक्म

वर्ष 1976 में सुखराम की मृत्यु पर सरपंच सरपंच से साज कर दिनांक 19/06/1976 के ग्रां.पं. में Succession हेतु प्रस्ताव पास करवा कर गलत नामान्तरकरण उक्त विवादित भूमिों का वारस भरवा लिया गया, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय की नजीर के अनुसार ग्रां.पं. द्वारा भरे गये नामान्तरकरण का कोई महत्व नहीं है। मत: प्रां.पं. अन्तर्गत 0.7 R.11 CPC भारी Cost के साथ जारी करमाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकॉर्ड, प्रस्तुत वस्तावेजात एवं माननीय उच्चस्थ न्यायालयों की नजीरों का अवलोकन किया गया तथा बहुलाय उभय पक्ष द्वारा वर-वक्त बहस प्रस्तुत की गई दलीलों पर मनन किया गया।



पूंछि पादिया ने प्रश्नगत भूमिों का वारस घोषणा, स्याई निवेद्याज्ञा एवं पुरुस्ती रिपोर्ट का दावा दिनांक 07/05/1979 को मृतक भैंरू द्वारा निष्पादित वसीयत को challenge करते हुए पैदा किया है। उक्त वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण भरा जाकर खातेदारी दर्ज हो चुकी है। पादिया उक्त वसीयत को संक्षम न्यायालय में चाराजोही कर शून्य धोषित करवाये, क्योंकि न्यायालय हाजा को वसीयत को शून्य धोषित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरी ओर वसीयतकर्ता भैंरू द्वारा वसीयत की गई भूमि, उसकी पुस्तैनी कही भी अभिलेखित नहीं की जादपत्र में न ही उक्त वसीयती नहीं किया गया है तथा में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पादपत्र के साथ संलग्न किया गया है।

→ माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने  
< भूपेन्द्र भाई एसमुख भाई बनाम सावित्री

बेन गेनूमल कृष्मानी AIR 2011 गुज 437 में यह अभिनिर्धारित किया है कि, "यह पश्चित करने हेतु कोई साक्ष्य नहीं है कि वादग्रस्त भूमि परस्तावेजी साक्ष्य की देखने पर पूर्णजी हो। अतः वाद निरस्त योग्य है।"

माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के उक्त न्यायाधिकृत वृष्टान्त तथा वादिया द्वारा अपने वादपत्र में विवादित भूमि परसी-यफ्तर्त की पैतृक भूमि होना अभिहित नहीं करने एवं विवादित भूमि का परसीयतकर्ता भूँके की पैतृक भूमि होने का कोई साक्ष्य (परस्तावेजी) वादपत्र के साथ संलग्न नहीं करने के परिप्रेक्ष्य में विवादित भूमि पर न्यायालय राजा का भ्रपणाधिकार नहीं पाया जाने पर, प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 07, नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता, स्वीकार किया जाकर वादपत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम ही तथा वाद तकमील दाखिल वफ़तर हो। निर्णय पुत्रे न्यायालय में सुनाया गया।

05/07/19

उपखण्ड अधिकारी  
हम्देला (सिकर)